on the use of 10 pesticides including DDT and BHC.

राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम

3818. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) कोई राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम नहीं है। तथापि जल संसाधनों के विकास हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अन्तरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के मध्य अलग-अलग सम्पर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की। कुल 36 जल अंतरण सम्पर्कों में से, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 सम्पर्कों और हिमालयी घटक के अन्तर्गत 19 सम्पर्कों का पता लगाया गया है। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 9 सम्पर्कों का कार्यालय अध्ययन पूरा किया जा चुका है। शेष सम्पर्कों का अध्ययन आठवीं योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रायद्वीपीय घटक के 9 सम्पर्कों और हिमालयी घटक के 3 सम्पर्कों का अन्वेषण भी इस अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

[3819. *Transferred to 17th December, 1992.]*

[3820. *Transferred to 16th December, 1992.]*

देश में फलों की पैदावार

3821. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फलों की वार्षिक अनुमानित पैदावार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने फल उत्पादकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश में फलों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 280 लाख मी॰ टन है।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार के पास किसानों की मदद करने के लिए "एक मण्डी हस्तक्षेप योजना" है, ताकि बागवानी जिन्सों के मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में हस्तक्षेप करके उत्पादों को कम मूल्यों पर बेचने से बचा जा सके। केन्द्रीय नोडल एजेन्सी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राज्य द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली सीमित मात्रा को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक विनिर्दिष्ट अवधि में निर्धारित मूल्यों पर खरीदने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसमें वे यह सहमति भी भेजते हैं कि इस योजना के प्रचालन में यदि कोई हानि होती है तो उसका 50% भार केन्द्र सरकार वहन करेगी।

(ii) वर्ष 1992 के लिए भारत सरकार ने अंगूर एवं किन्नू/माल्टा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार घोषित की है:

क्रि॰	राज्य	लक्षित मात्रा (मीटरी टन में)	खरीदी गयी मात्रा (मीटरी टन में)	बाजार हस्तक्षेप योजना की दर
1 अंगूर	हरियाणा	2,000	3.75	पिछले 5 वर्षों के
	पंजाब	2,000 (जून 92)	—	औसत एवं 10% बाजार दर